



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]
No. 49]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 2000/फाल्गुन 28, 1921
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 2000/PHALGUNA 28, 1921

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संशोधन

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2000

सं. ए-45012 (2)/98-प्रशा. 3 (वि.का.)—“संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग” के गठन के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2000 को जारी संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए,—

(i) पैरा 3 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“आयोग के अध्यक्ष को 33,000/- रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। यदि वे सरकारी पेंशनर हैं, तो वे अपनी पेंशन की राशि को घटाकर मानदेय प्राप्त करने के पात्र होंगे/होंगी। यदि आयोग के अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे/होंगी, तो उनकी सेवा शर्तें वही होंगी जो सेवारत भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश को देय टाइप का सरकारी आवास प्राप्त करने के हकदार होंगे।”

(ii) पैरा 6 के पश्चात् पैरा 6क निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“6क.—उपर्युक्त पैरा 5 और 6 में अन्य बातों के होते हुए भी, आयोग का सदस्य, जोकि संसद सदस्य है, संसद (निर्हरता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित भत्तों के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक अथवा भत्ते का पात्र नहीं होगा।”

आर.एल. मीना, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

AMENDMENT

New Delhi, the 17th March, 2000

No. A-45012(2)/98-Admn. III(LA).—In partial modification of the Resolution dated 22-2-2000, providing for constitution of the 'National Commission to Review the Working of the Constitution',—

(i) para 3 shall be substituted as under :—

"The Chairperson shall be paid a consolidated honorarium of Rs. 33,000/- per month. In case he or she is Government pensioner, he or she will be entitled to such honorarium minus pension. In case the Chairperson is a retired Chief Justice of India, his or her conditions of service will be the same as applicable to a serving Chief Justice of India. The Chairperson shall be entitled to Government accommodation for residence of the type which is serving Chief Justice of India is entitled to."

(ii) after para 6, para 6A shall be added as follows :—

"6A. Notwithstanding anything contained in paras 5 and 6 above, a Member of the Commission, who is a Member of Parliament, shall not be entitled to any remuneration or allowance other than the allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959."

R.L. MEENA, Secy.